



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 रोहित आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे

6 मौलिक कर्तव्यों की अनदेखी क्यों?

7 ईशा कोपिकर निभा रही हैं एक स्नेही मां का किरदार

फ़र्स्ट टेक

ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी ने ईरान को प्रतिबंध की धमकी दी

बर्लिन/एपी। ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों के साथ वार्ता इस महीने के अंत तक पुनः शुरू करने और संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग करने की समय-सीमा करीब आने के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शीर्ष राजनयिकों ने ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। 'ई3' के नाम से जाने जाने वाले तीनों देशों ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में कहा कि वे स्नेहबैक तंत्र के नाम से जानी जाने वाली प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो पश्चिमी पक्षों में से किसी एक को उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की अनुमति देता है, जब तेहरान इसकी आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल येरोट ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह पत्र पोस्ट किया। उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिकों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका पर सार्वजनिक ऋण रिकॉर्ड 37,000 अरब डॉलर

वॉशिंगटन/एपी। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड 37,000 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 'कांग्रेस का बजट कार्यालय' ने जनवरी 2020 में अनुमान लगाया था कि अमेरिका यह स्तर वित्त वर्ष 2030 के बाद ही छुएगा। लेकिन कर्ज उम्मीद से तेजी से बढ़ा। कर्ज बढ़ने का कारण कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का बंद होना तथा ट्रंप तथा बाइडन प्रशासन ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिए।

दक्षिण कोरिया: पूर्व राष्ट्रपति यून की पत्नी भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार

सियोल/एपी। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल की पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी उनके खिलाफ रिश्तखोरी, स्टॉक में हेराफेरी और एक उम्मीदवार के चयन में दखलंदाजी सहित विभिन्न आरोपों की जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी वारंट के लिए विशेष अभियोजक के अनुरोध को मंगलवार देर रात स्वीकार करते हुए 'सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' ने कहा कि यून की पत्नी किम कियोन सबूतों को नष्ट कर सकती हैं। लिबरल पार्टी की नई सरकार श्रा किम के खिलाफ शुरू कराई गई यह जांच तीन विशेष अभियोजक पड़तालों में से एक है।

14-08-2025
सूर्योदय 6:41 बजे

BSE 80,539.91 (+304.31)
NSE 24,619.35 (+131.95)

सोना 10,637 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम
चांदी 118,456 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दलित कौन

पद पैसा रूतबे वाले भी, कह दलित स्वयं को चले दौंवा।
वोटों या निज हित के खातिर, फैलाते नफरत मनमुटाव।
जो दलित कह रहे हैं खुद को, करते आपस में भेदभाव।
ना होती जाति दलित सारी, है व्यक्ति दलित जिसके अभाव।।

वैश्विक अशांति से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता भरे दौर का सामना कर रहे हैं, जहां कोविड महामारी, कई संघर्षों और व्यापार में बड़े बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वैश्विक अशांति से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता की मानसिकता होनी आवश्यक है।

जयशंकर ने यहां एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा, "वैश्वीकरण और शहरीकरण के युग में परंपराएं अक्सर समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन हमने इन्हें संजोकर भारतीय पर्यटन को और भी अधिक आकर्षक बना दिया है।"

कार्यक्रम के विषय 'अजेय भारत की भावना' की ओर इशारा करते हुए जयशंकर ने



■ हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जीत हासिल की है और प्रगति एवं समृद्धि की यात्रा में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है।

कहा, हम एक सभ्यतागत राष्ट्र हैं, ऐसा राष्ट्र और समाज जिसने अक्सर समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन हमने इन्हें संजोकर परंपराओं और विरासत को संजोकर रखा है।

विदेश मंत्री ने कहा, "हमारी असली ताकत हमारे लोग रहे हैं। हमारे लोग और

उनका आत्मविश्वास। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी जीत हासिल की है और प्रगति एवं समृद्धि की यात्रा में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है।" फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी' ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया

था। उन्होंने किसी भी देश का नाम लिए बगैर कहा, "हम निश्चित रूप से एक उथल-पुथल भरे और अनिश्चित दौर में रह रहे हैं, जिसमें कोविड महामारी, अनेक संघर्षों (जिनमें से कई अब भी जारी हैं) और व्यापार में बड़े बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है।"

मंत्री ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग वाले देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और जाहिर है कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे समय में मजबूत पर्यटन क्षेत्र का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आखिरकार, इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, उद्यमिता, रचनात्मकता, कौशल वृद्धि और रोजगार सृजन जैसी कई व्यापक संभावनाएं शामिल हैं।

जयशंकर ने कहा कि वास्तव में कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था को उर्जा प्रदान करने और रोजगार बढ़ाने में अधिक योगदान देती हैं।

पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80 फीसदी पानी देकर

कांग्रेस ने देश के साथ बेईमानी की : शिवराज सिंह चौहान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भोपाल/भाषा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को देकर देश के साथ बेईमानी की थी जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लेकिन सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया।

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान जाने के एक दिन बाद, भारत ने पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। उन्होंने यह सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा नेहरू ने पाकिस्तान को पानी दिया और पैसे भी दिए लेकिन वहां से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की।

उन्होंने कहा, हमने आतंक के अड़े सटीक निशाना लगाकर खंडहर में बदल दिए। उन्होंने



नेहरू जी (जवाहरलाल नेहरू) ने भी बेईमानी की। हमारी सिंधु, झेलम, विनाब का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। उन्होंने यह सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा नेहरू ने पाकिस्तान को पानी दिया और पैसे भी दिए लेकिन वहां से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की।

उन्होंने कहा, हमने आतंक के अड़े सटीक निशाना लगाकर खंडहर में बदल दिए। उन्होंने

हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा, हमने आतंक के आकाओं की लाशों के डेर पाकिस्तान में लगा दिए और पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दिया।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव को सफलता से अंजाम दिया। उन्होंने कहा, ये आज का भारत है, जो दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। अभी पड़ोसी देश ग्रीवड भभकियां दे रहा है। भारत किसी भी ग्रीवड भभकी से डरने वाला नहीं है।

एसआईआर विवाद पर न्यायालय ने कहा

मतदाता सूची स्थिर नहीं बनी रह सकती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस दलील से असहमति जताई कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाता सूची "स्थिर नहीं" बनी रह सकती।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिसॉर्सेस' (एडीआर) ने दलील दी कि देशभर में इस कवायद के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एनजीओ के अलावा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया



को चुनौती दी है। एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि एसआईआर पर निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को कानूनी आधार के अभाव में और कानून में कभी भी विचारणीय नहीं होने के कारण रद्द कर देना ज़रूरी है। उन्होंने दलील दी कि इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग अपनी स्थापना के बाद से कभी भी ऐसी कोई कवायद नहीं कर सका और यह पहली बार किया जा रहा है और अगर ऐसा होने दिया गया तो केवल ईश्वर ही जानता है कि इसका अंत कहां होगा।

पीठ ने कहा, इस तर्क से तो विशेष गहन पुनरीक्षण कभी नहीं किया जा सकता। एक बार की कवायद केवल मूल मतदाता सूची के लिए की जाती है। हमारे विचार से मतदाता सूची कभी स्थिर नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने कहा, इसमें संशोधन होना ही चाहिए, अन्यथा निर्वाचन आयोग उन लोगों के नाम कैसे हटाएगा जिनकी मृत्यु हो गई है, पलायन कर चुके हैं या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं?" पीठ ने शंकरनारायणन से कहा कि निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कवायद करने का अधिकार है, जैसा वह उचित समझे। न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 21(3) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि "निर्वाचन आयोग किसी भी समय, कारणों को दर्ज करके, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र का निर्देश दे सकता है...। न्यायमूर्ति बागची ने शंकरनारायणन से पूछा, जब प्राथमिक कानून कहता है कि 'ऐसे तरीके से जो उचित समझा जाए, लेकिन अधीनस्थ कानून ऐसा नहीं कहता...।

अमेरिका में हिंदू मंदिर विरूपित किया

न्यूयॉर्क/भाषा। अमेरिका के इंडियाना शहर में एक हिंदू मंदिर के नामपट्ट को विरूपित कर दिया गया जिसे भारतीय वाणिज्य दूतावास ने "निंदनीय" बताया है। मंदिर के आधिकारिक जनसंपर्क हैंडल ने मंगलवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि यह "घृणित कृत्य" ग्रीनवुड शहर स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में हुआ। इसमें कहा गया है कि एक साल से भी कम समय में यह चौथी बार है जब किसी बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया है। शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस कृत्य पर कड़ा संज्ञान लिया और इसे "निंदनीय" बताया। उसने 'एक्स' पर कहा, इंडियाना के ग्रीनवुड स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य नामपट्ट का अपमान निंदनीय है। दूतावास ने कहा कि उसने "शीघ्र कार्रवाई" के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया है। इसमें कहा गया है कि महावाणिज्य दूत ने ग्रीनवुड के मेयर सहित श्रद्धालुओं और स्थानीय नेतृत्व की एक सभा को भी संबोधित किया और "वहाँ एकता एवं एकजुटता तथा उपद्रवियों के विरुद्ध सतर्कता बरतने का आह्वान किया।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा

आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिका पर गौर किया जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने आवारा कुत्तों से संबंधित एक याचिका का उच्चतम न्यायालय में तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर बुधवार को आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे।

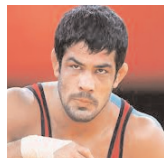
प्रधान न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति के. जिनोद चंद्रा की पीठ के समक्ष एक वकील ने 'कॉन्ग्रेस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)' की याचिका का उल्लेख किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक अन्य पीठ आवारा कुत्तों के संबंध में एक आदेश पहले ही पारित कर चुकी है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सोमवार को कहा था कि कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों की संख्या समय के साथ बढ़ानी होगी। न्यायालय ने दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे छह से आठ सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाएं।

स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। वकील ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अगुवाई वाली पीठ श्रा मई 2024 में पारित उस आदेश का बुधवार को हवाला दिया, जिसमें आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह इस पर गौर करेंगे।

'कॉन्ग्रेस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)' की याचिका में दावा किया गया है कि उस पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का पालन नहीं किया जा रहा जिसमें आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नियमित बधियाकरण और टीकाकरण कार्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं। न्यायालय ने सोमवार को कहा था कि कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों की संख्या समय के साथ बढ़ानी होगी। न्यायालय ने दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे छह से आठ सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाएं।

पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द शीर्ष अदालत ने आत्मसमर्पण को कहा

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के चन्नलाम स्टेटियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ऑलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के चार मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी। ऑलंपिक पदक विजेता को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ श्रा दायर की गई उस अपील पर आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के कुमार को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी थी। कुमार और अन्य पर एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई 2021 में धनखड़ पर छत्रसाल स्टेटियम में जानलेवा हमला करने का आरोप है।



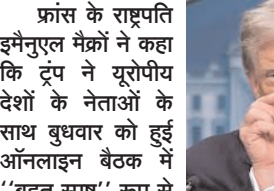
अगर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो उन्हें 'गंभीर परिणाम' भुगतने पड़ेंगे: ट्रंप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

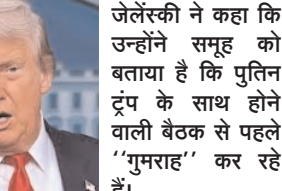
वॉशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अलास्का में शुक्रवार को होने वाली वार्ता में यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो उन्हें इसके "बहुत गंभीर परिणाम" भुगतने पड़ेंगे।

बिहार में ईडी ने फिर की छापेमारी

पटना/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार में कथित अवैध शराब तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में बुधवार को फिर से छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर, हरियाणा के गुरुग्राम, अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन और नामसाई तथा झारखंड के रांची में कम से कम सात स्थानों पर तलाशी ली जा रही है।



फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा कि ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बुधवार को हुई ऑनलाइन बैठक में "बहुत स्पष्ट" रूप से कहा है कि अमेरिका अलास्का में आगामी अमेरिका-रूस शिखर सम्मेलन में संघर्ष विराम समझौता चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर



जेलेन्स्की ने कहा कि उन्होंने समूह को बताया है कि पुतिन ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से पहले "गुराह" कर रहे हैं।

जेलेन्स्की ने कहा कि पुतिन "यूक्रेनी मोर्चे के सभी क्षेत्रों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं" ताकि यह दिखाया जा सके कि रूस "पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने

अमेरिकी शुल्क का प्रभाव छह महीने से ज्यादा टिकने वाला नहीं : सीईए नागेश्वरन

मुंबई/भाषा। मुख्य आर्थिक नागेश्वरन (सीईए) की. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से जुड़ी चुनौतियां ज्यादा टिकने वाली नहीं हैं और एक या दो तिमाहियों में समाप्त हो जाएंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि देश अन्य दीर्घकालिक चुनौतियों से जूझ



रहा है और उन्होंने इससे निपटने के लिए निजी क्षेत्र से और अधिक

प्रयास करने का आग्रह किया। नागेश्वरन ने वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर में आई नरमी के लिए कर्ज से जुड़ी कड़ी स्थिति और नकदी की समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया।

वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रही जो एक साल पहले 9.2 प्रतिशत थी।

महाभियोग से बचने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा के पास इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प: नियम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है और ऐसे में संसद श्रा पद से हटाए जाने से बचने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प बचा है। जांच समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन न्यायास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे।

बिरला ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रस्ताव (न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का) लंबित रहेगा। उन्होंने सदन को सूचित किया कि उन्हें गत 31 जुलाई को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 146 सदस्यों श्रा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा था कि उक्त सूचना में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया से अवगत अधिकारियों ने बताया कि किसी भी सदन में सांसदों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति वर्मा यह घोषणा कर सकते हैं कि वह पद छोड़ रहे हैं और उनके मौखिक बयान को उनका



इस्तीफा माना जाएगा। यदि वह इस्तीफा देने का फैसला करते हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बराबर पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि लेकिन स्थित आधिकारिक आवासीय परिसर से मार्च में अद्यजली नोटों की गड़ियां मिलने के बाद उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति खन्ना की रिपोर्ट मामले की जांच करने वाले तीन न्यायाधीशों के आंतरिक पैनल के निष्कर्षों पर आधारित थी। सूत्रों ने पूर्व में बताया

था कि न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, जब किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में स्वीकार कर लिया जाता है, तो (लोकसभा) अध्यक्ष या सभापति, जैसा भी मामला हो, तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। समिति उन आधारों की जांच करेगी, जिनके तहत न्यायाधीश को पद से हटाने (या दूसरे शब्दों में, महाभियोग) की मांग की गई है। समिति में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, 25 उच्च न्यायालयों में से एक के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायविद शामिल होते हैं। नियम के अनुसार, एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और फिर समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

संघर्ष (जम्मू कश्मीर)/भाषा।आई-संचालित प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के कारण बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए सेना जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्मार्ट बाड़, रोबोटिक म्यूल और दुर्गम इलाकों में चल सकने वाले वाहनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग



एलओसी पर सीमा सुरक्षा मजबूत कर रही स्मार्ट बाड़, रोबोटिक म्यूल और विशेष वाहन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

क्राडकोंटर, उन्नत निगरानी उपकरण, बुलेटप्रूफ वाहन, आधुनिक हथियार और अंधेरे में देखने में सहायक उपकरण सहित अन्य उपकरणों का 7 से 10 मीटर के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुंदरबनी के दूरदराज के क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के अदम्य साहस को देखने के लिए मीडियाकर्मीयों को एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हुए सेना ने इस

समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है तथा सीमा पर गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि 'आर्मडो' और सभी प्रकार के वाहनों जैसे उन्नत सैन्य वाहनों को शामिल किए जाने से सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सबसे चुनौतीपूर्ण और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी, ताकि वे किसी भी खतरे को, विशेष रूप से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों से उत्पन्न खतरे को बेअसर कर सकें।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए 'पेड पोस्ट' चिन्हित करें मीडिया कंपनियां : एससीआई मुंबई/भाषा। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एससीआई) ने मीडिया कंपनियों से बुधवार को कहा कि वे अपने सोशल मीडिया खातों पर साझा किए जाने वाले 'पेड पोस्ट' को चिन्हित करें।

विज्ञापन उद्योग के स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) ने विज्ञापनों को संपादकीय सामग्री समझे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। परिणामस्वरूप, उसने ऐसे विज्ञापनों को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए अपनी संहिता में एक प्रावधान जोड़ा है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि नए जोड़े गए खंड के तहत किसी भी मीडिया कंपनी श्रा 'पेड' या प्रायोजित सामग्री के शुरू में ही यह स्पष्ट करना होगा, ताकि दर्शकों को पहले से पता चल जाए कि यह प्रचाराल्पक प्रकृति का है। बयान में कहा गया, विज्ञापन, साझेदारी, मुफ्त उपहार, प्रायोजित, प्लेटफॉर्म डिस्कलोजर टैग" और "सहभागिता" स्वीकार्य चिह्न (लेबल) हैं।

उच्च संपादकीय विश्वसनीयता वाले मंचों पर भ्रामक या अघोषित प्रचार के बारे में उपभोक्ता शिक्षायें मिली थीं जिसके कारण नया खंड शामिल किया गया। एससीआई की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं महासचिव मनीषा कपूर ने कहा, कई मीडिया संस्थान नियमित रूप से अपने सोशल मीडिया खातों पर संपादकीय सामग्री साझा करते हैं।



राष्ट्र निर्माण में सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी : न्यायमूर्ति हेगड़े

अपने आप में अनुकरणीय है कलिंगा शैक्षणिक संस्थान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर। केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत आने वाले कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान(केआईएसएस), कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान(केआईआईटी) और कलिंगा आयुर्विज्ञान संस्थान के दो दिनेसीय दौर पर आए न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने स्कूल ऑफ लॉ ऑडिटोरियम में आयोजित 'सामाजिक मूल्यों का हास और उसके परिणाम' विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि समाज में सामाजिक मूल्यों का हास हो रहा है, जिसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा नहीं मिल रही है। हर पेशे में मूल्यों का हास हो रहा है। इसके कारण भ्रष्टाचार सहित कई ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मूल्यों की पुनर्स्थापना आज की आवश्यकता है। भ्रष्टाचारियों में कानून का कोई डर नहीं है। शिक्षित वर्ग में यह अभिशाप

बढ़ता जा रहा है, यह और भी चिंताजनक है। शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा के साथ-साथ छात्रों में एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र आज अत्यधिक विकास कर रहा है और राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका अद्वितीय है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने 1860 से अधिक स्कूलों और शिक्षण संस्थानों का दौरा किया है, जिनमें से कलिंगा शिक्षण संस्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों को व्यापक शिक्षा मिल रही है। आदिवासी समुदाय, गरीब और नेत्रहीनों सहित सभी को एक ही छत के नीचे व्यापक शिक्षा मिल रही है। यह 20 हजार से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक विशाल शैक्षणिक कोष है। यह सराहनीय है कि बड़ी संख्या में गरीब लोगों को मुफ्त भोजन, आवास और शिक्षा मिल रही है।

कबूतरों को दाना डालने के मामले में बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए : फडणवीस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने को लेकर उठे विवाद को सुलझाने के लिए लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए।

उन्होंने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कुछ लोग कबूतरों को दाना डालने के मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। फडणवीस ने कहा कि वे इन प्रयासों में सफल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कबूतरों को दाना डालने के लिए ऐसे स्थान बनाए जाएं जहां मानव बस्तियां न हों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने स्वास्थ्य



संबंधी खतरों का हवाला देते हुए दावर में एक लोकप्रिय स्थल समेत कबूतरखानों (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को बंद कर दिया है। इस फैसले का एक तबके ने विरोध किया है।

फडणवीस ने दावर में स्थित कबूतरखाना बंद होने के बारे में पूछे जाने पर कहा, दो बातें स्पष्ट हैं - लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। कुछ मुद्दे आस्था से भी जुड़े हैं। हम दोनों का ध्यान रख सकते हैं और कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हम ऐसे स्थान बना सकते हैं जहां कोई भी मानव बस्ती न हो। इस समस्या के समाधान के कई तरीके हैं।

दूषित पानी पीने से आदिवासी स्कूल के कई छात्र बीमार

दूषित पानी पीने से आदिवासी स्कूल के कई छात्र बीमार

चंद्रपुर/भाषा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक सरकारी आदिवासी स्कूल के कम से कम 80 छात्र दूषित तौर पर दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रभावित बच्चे चिमुर् के जम्बुलघाट में स्थित आदिवासी आश्रम स्कूल के छात्र हैं।

अधिकारी ने बताया, रविवार को स्कूल में दूषित पानी पीने से कम से कम 70-80 छात्र बीमार हो गए। उन्होंने उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की। आठ छात्रों को गंभीर हालत में चिमुर् के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से छह को छुड़ी दे दी गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पहले ही इलाके का निरीक्षण कर लिया है और पंचायत समिति से आश्रम स्कूल के पानी का स्रोत को बदलने को कहा है।

भारत अमेजन की वृद्धि में बड़े योगदान वाले देशों में शामिल होने की राह पर: शीर्ष अधिकारी amazon

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बुधवार को कहा कि भारत कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक बनने की राह पर है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। अमेजन के भारतीय कारोबार प्रमुख समीर कुमार ने कहा कि उनकी कंपनी भारत में अपने निवेश एवं ध्यान को दोगुना कर रही है और अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। कुमार ने कहा कि भारत में ऑनलाइन उपभोग की प्रवृत्ति अभी बहुत गहरी नहीं हुई है जिससे कंपनी के लिए 'बहुत बड़ा अवसर' मौजूद है। उन्होंने बताया कि अमेजन 2025 में ही करीब 2,000 करोड़ रूपए का निवेश भारतीय परिचालन पर करेगी।

कंपनी वर्ष 2030 तक भारत में कुल 26 अरब डॉलर निवेश की योजना पहले ही घोषित कर चुकी है, जिसमें से 2023 से 2030 के बीच लगभग 15 अरब डॉलर निवेश किए जाने हैं। कुमार ने भारत को अमेजन के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताते हुए कहा, लंबी अवधि में हमें पूरा विश्वास है कि भारत हमारी वृद्धि में प्रमुख योगदान देगा। उन्होंने कहा कि देश

के करीब एक अरब मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में से अभी 10 करोड़ लोग ही ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऐसे में अगले 20 करोड़ खरीदारों तक पहुंचना कंपनी का लक्ष्य है। कुमार ने कहा कि आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी और खपत बढ़ने के साथ भारत में ऑनलाइन खरीदारी को महत्व देने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। अमेजन की नजर अब दूसरी, तीसरी श्रेणी के शहरों और उससे आगे तक फैले व्यापक बाजार पर है। कुमार ने कहा कि कंपनी विक्रेताओं के लिए घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम बहुत दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और भारत में अभी बहुत काम बाकी है। उन्होंने हाल ही में बेंगलूर और दिल्ली में शुरू की गई त्वरित आपूर्ति सेवा 'अमेजन नाउ' को ग्राहकों से जबरदस्त समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि कंपनी की इस सेवा को देश के अन्य शहरों में भी ले जाने की योजना है।

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मोहला (छत्तीसगढ़)/भाषा। छत्तीसगढ़ के मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी जिले में बुधवार को

सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ मदनवाड़ा इलाके के जंगल में उस समय हुई जब सुरक्षाबलों का एक दल नक्सल विरोधी अभियान पर

निकला था। उन्होंने बताया कि गोलीबारी बंद होने के बाद, घटनास्थल से दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में खोज अभियान जारी है। इस संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

एफटीए पर बातचीत पूरी दृढ़ता, बराबरी पर करता है भारत: जितिन प्रसाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदले हुए भारत में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत पूरी दृढ़ता और बराबरी के आधार पर की जाती है, तो उनसे बराबरी के आधार पर बात करते हैं। यह नया भारत है, हम अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं।

उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत... अमेरिका, यूरोपीय संघ, पेरू, ब्रिटीश और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है। अमेरिका के साथ भारत की अबतक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में



कोई भी समझौता संभव नहीं है। प्रसाद यहां श्रमका स्थित बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) की नवनिर्मित विस्तारित इमारत के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीपूष गोयल ने कहा कि नवाचार बौद्धिक संपदा का एक रूप ही नहीं, बल्कि संप्रभुता का प्रतीक भी है और यह भारत को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक विकसित देश में नवाचार, नए विचार, शोध एवं विकास प्राथमिकताएं रही हैं और ऐसे नवाचार के माध्यम से ही ये राष्ट्र समृद्ध हुए हैं।

उच्च शुल्क के खिलाफ किसानों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूँके

इंजौर/भाषा। भारत से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका के घोषित उच्च शुल्क के खिलाफ विरोध जताते हुए मध्यप्रदेश के कई स्थानों पर किसानों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूँके। संयुक्त किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी।

यह विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों के अखिल भारतीय आह्वान पर किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष बादल सरोज के मुताबिक कृषकों ने राज्य के करीब 40 जिलों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पुतले जलाए गए। उन्होंने कहा, "भारत से आयातित वस्तुओं पर ट्रंप का घोषित उच्च शुल्क भारतीय किसानों और मजदूरों के हितों के सरासर खिलाफ है। ट्रंप अमेरिकी माल को भारत में किसी भी तरह खपाना चाहते हैं, जबकि भारत से उनके देश को होने वाले निर्यात को रोकना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की अनुचित सोदेबाजियां नहीं होनी चाहिए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्रालय ने विभिन्न जोन से कहा है कि यदि मांग और औचित्य हो तो वे ई-नीलामी के जरिये विभिन्न स्टेशन पर एकल ब्रांड, कंपनी के स्वामित्व वाली प्रीमियम दुकान के लिए स्थान आवंटित कर सकते हैं। मंत्रालय ने 11 अगस्त, 2025 को जारी एक आधिकारिक पत्र में हवाई अड्डों की तर्ज पर प्रीमियम एकल ब्रांड दुकानें खोलने के संबंध में दिशा-निर्देशों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के प्रस्ताव का जवाब दिया। इसमें कहा गया कि मामले की जांच करने के बाद यह

निर्णय लिया गया है कि दुकानें मौजूदा नीति के तहत आवंटित की जा सकती हैं न कि नामांकन के आधार पर।

मंत्रालय ने कहा, संबंधित मंडल/जोन यात्रियों की संख्या, स्थानी की उपलब्धता, यात्री जनसांख्यिकी और अन्य प्रासंगिक स्टेशन-विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर प्रीमियम स्थानों और उपयुक्त उत्पाद/सेवा श्रेणियों की पहचान करेंगे।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि दुकानों का आवंटन ई-नीलामी नीति के अनुसार किया जाएगा। उसने कहा, ऐसे ठेके देने के लिए, ई-नीलामी मॉड्यूल के भीतर एक समर्पित "प्रीमियम स्टोर्स" खंड बनाया जा सकता है। सफल

बोलीदाता आउटलेट के लिए ब्रांड/ब्रांडों का निर्णय ले सकता है। पत्र में कहा गया कि जोन सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी दुकानें स्टेशन के माहौल और भारतीय रेलवे की छवि को बेहतर बनाए।

मंत्रालय ने कहा, संबंधित मंडल आवश्यकतानुसार अनुबंध की विशेष शर्तें तैयार कर सकते हैं। इससे पहले, दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि उसके कई स्टेशन के पुनर्विकास कार्य, प्रमुख उन्नयन और एबीएसएस (अमृत भारत स्टेशन योजना) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

एससीआर ने इसी के साथ इस संबंध में मंत्रालय से दिशानिर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया था।

भारतीय शिक्षण संस्थानों पर 9 महीने में 2 लाख से अधिक साइबर हमले, चार लाख डाटा में सेंध की कोशिश

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय शिक्षण संस्थानों को महज नौ महीनों में दो लाख से अधिक बार साइबर हमलों और जानकारी में सेंध लगाने की कोशिश चार लाख कोशिशों का सामना करना पड़ा है। यह खुलासा एक प्रायोगिक अध्ययन में हुआ है।

'भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए साइबर खतरों और डिजिटल जोखिमों की तलाश' शीर्षक से यह अध्ययन साइबरपर्स फाउंडेशन के महत्वकांक्षी ई-कवच पहल के तहत डेलनेट, रीसिक्वोरिटी और ऑटोबोट इन्फोसेक के सहयोग से किया गया है। इस अध्ययन रिपोर्ट को बुधवार साइबर फस्ट रिसर्पॉन्स' पहल की शुरुआत के साथ जारी किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों, संकाय, पुस्तकालयाध्यक्षों और कर्मचारियों को साइबर खतरों, डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए कुशल बनाना है।

जुलाई 2023 और अप्रैल 2024 के बीच किए गए नौ महीने के अध्ययन में पाया गया कि 8,000 से ज्यादा विशिष्ट सूत्रनेम और 54,000 विशिष्ट पासवर्ड 'ब्रूट-फोर्स' हमलों (इसमें साइबर हमलावर कई संभावित कुंजी या पासवर्ड का इस्तेमाल कर डाटा तक पहुंचने की कोशिश करता है)में इस्तेमाल किए जा रहे थे। आम तौर पर लक्षित यूजरनेम में 'रूट' और 'एडमिन' शामिल थे, जबकि '123456' और 'पासवर्ड' जैसे कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल अक्सर किया जा रहा था। अध्ययन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि, भारतीय शैक्षणिक संस्थान पर मजबूत साइबर सुरक्षा वाले समकक्षों की तुलना में जानकारी में सेंधमारी की आशंका पांच गुना अधिक है।



चिकित्सा अधीक्षक एवं राजभाषा प्रमर्शी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा कि हिंदी के पुस्तकें एवं प्रतिभागिता प्रमण-पत्र वितरित किए। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को काफी उपयोगी एवं रुचिकर बताया। उन्होंने आगामी माह होने वाले हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली हिंदी प्रतिभागिताओं में भी जाहिरात करने की अपनी इच्छा जताई की। कार्यशाला में राजभाषा हिंदी के संशोधनकर्ता प्रवाधनाथ, प्रशासनिक सहायक, नेमी टिप्पणियों का अध्यास, प्रभाव तथा हिंदी रिपोर्ट भरने के बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संवादन कण्ठि अनुवाद अधिकारी कैलाश चंन शर्मा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

और रेजिमेंटल परंपराओं के अलावा सैनिकों के जीवन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन समूह फोटोग्राफ और जलपान के साथ हुआ।

भाईचारे का संदेश गर्व से फैलाया। यह रैली राष्ट्र की सुरक्षा और उसके मूल्यों को बनाए रखने के प्रति रेलवे सुरक्षा बल की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

‘परम सुंदरी’ एक रोमांटिक-कॉमेडी क्रॉस-कवचरल लव स्टोरी है, जो उत्तर भारतीय और साथ्य इंडियन मलती के बीच की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। फिल्म की शूटिंग केरल में हुई है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा (परम) और जान्हवी कपूर (सुंदरी) मुख्य भूमिकाओं में हैं। ट्रेजर में दिवली के एक खूबसूरत लड़के और केरल की एक खूबसूरत लड़की की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। यह कहानी सांस्कृतिक अंतर को कॉमेडी और ड्रामा के साथ पेश करती है। केरल के खूबसूरत बैकग्राउंड, बारिश से भीगी सड़कें और प्राचीन चर्चों की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई यह कहानी इसी साल दशकों के सबसे आणखी 2 मिलद

40 सेकंड के ट्रेनर में सिद्धार्थ और जाह्नवी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है। सिद्धार्थ का पंजाबी स्टायल और जाह्नवी का दिक्कत भारतीय लुक कहानी में आकर्षण को जोड़ता है। ट्रेनर की शुरुआत एक वर्च में होती है, जहां सिद्धार्थ और जाह्नवी प्रेम में डूबे प्रेम करते हैं। प्रेम बताता है कि दुनिया में लगभग 810 करोड़ लोग हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों से प्रेम होता है, यही सच्चा प्रेम कहलाता है। यही नहीं, वे दक्षिण भारत की संस्कृति को अपनाने भी नजर आते हैं। फिल्म के कई गाने पहले ही जारी हो चुके हैं। इसमें 'परदेसिया' और 'सोना साड़ी' का नाम शामिल है। सिद्धार्थ महताब और जाह्नवी कपूर के साथ ही फिल्म में संजय कपूर और भोजपति सिंघ जैसे कलाकार भी अलग भूमिकाओं में हैं।

कहा, हम अक्सर वृद्ध दाताओं के अंगों के महत्व को कम आंकते हैं। लेकिन कड़ी जाँच और शल्यक्रिया के बाद की सावधानीपूर्वक देखभाल से, ये अंग प्राप्तकर्ता को, यहाँ तक कि उनके बुढ़ापे में भी, कई वर्षों तक गुणवत्तापूर्ण जीवन

धमकियां दे रहे हैं। धमकियों का भारत-वर्ष पर कोई असर नहीं होगा। बहुत ही गव्वा।”

ओवैसी ने संधि पर शरीफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर और अन्य नेताओं की टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही।

शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि भारत को पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीनने नहीं दी जाएगी।

पहलामान में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई डॉडजलम कानून कदम उठाए, जिन्हें 1960 की कानून संहिता को स्थगित करना भी शामिल था। विहार में विशेष गहन-पुनरीक्षण अभियान पर हैदराबाद के महासचिव ने आतंकी कि कई वादे मंजवादाओं के नाम ढट्टा ज़ा रहे हैं।

लॉन्ड्रिंग, रोकथाम अधिनियम (पीएलएनए) के तहत जांच शुरू की है, जो तेलंगाना और गुफरा प्रदेश में दर्ज पांच एफआईआर पर आधारित है। मार्च 2024 में साइबरबाद पुलिस ने निजि देवरकोंड, राणा दमुगुती, प्रकाश राज और अन्य के खिलाफ सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया था। राणा और विजय ने दावा किया कि उन्होंने केवल कानूनी ऑनलाइन उच्छेदन-बेरेड गेम्स का प्रचार किया। विजय देवरकोंड ने 6 अगस्त को पूछाछा के बाद कहा कि उन्होंने एक गेमिंग ऐप का प्रचार किया था, जो सरकार द्वारा मामला प्राप्त और लाइसेंस प्राप्त है। उन्होंने अपने खाते, कंपनी और वित्तीय लेनदेन की जानकारी दी। वहीं, प्रकाश राज ने बताया कि उन्होंने 2016 में एक गेमिंग ऐप का विज्ञापन किया था, लेकिन नैतिक कारणों से कोई भुगतान नहीं लिया और बाद में इसका प्रचार बंद कर दिया। इडम इस मामले में वित्तीय लेनदेन और प्रचार गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है।

जिसमें पड़्डा 64वें और पांडे 75वें क्रम पर स्थान पर हैं। पांडे ने कहा कि यहां उनसे करियर का पहला पुरस्कार है और सीधे तौर पर दर्शकों की प्रतिक्रिया से ये मिलना और भी खास बात है। उन्होंने यशराजज्ज पिल्मस्, आदित्य चोपड़ा और सूरशी भट्टा की भन्यपाद किया। पांडे ने कहा, अइन्पादीबी की हत्सा बनना, इससे सम्मानित होना हिस्सा की बात है।

पड्डा ने कहा, मुझे खुशी है कि 'सैयारा' और उसमें मेरे अभिनय ने दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित

नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करने में देशाभोग रहे। वही ईशा कोम्पिकर ने एक बार फिर युवा प्रतिभाओं के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। अभिनेत्री, जो नए और अपरिचित टैलेंट को बढ़ावा देने की पुरजोर समर्थक रही हैं, उन्होंने एक बार फिर सुभाष घई के प्रतिष्ठित संस्थान व्हिसलिंग बुक्स इंटरनेशनल अकेडमी में फिल्म निर्माण के छात्रों को अपना प्यार और समर्थन देकर यह सिद्ध किया है। यह प्रतिभाशाली अभिनेत्री छात्रों के डिप्लोमा प्रोजेक्ट 'रॉकेटशिप' में अभिनय कर उन्हें अपनी अनुभवपूर्ण उपस्थिति और स्टाइल पॉवर के जरिये सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे इन नवोदित फिल्मकारों की रचनात्मक दृष्टि को साकार करने में मदद मिली है।

और इसके बाद कुत्ते शांत हो जाते हैं, उनके खूँखार होने और काटने की घटनाएँ कम हो जाती हैं। चूंकि कुत्ते अपने इलाके का पहाती हैं, इसलिए वे बिना नसबंदी और बिना टीकाकरण वाले कुत्तों को अपने इलाके में घुसने नहीं देते।

अभिनेता अनुसार, सार्वजनिक स्थानों से आवाका कुत्तों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

आवाका कुत्तों के काटने से, विशेष रूप

से बच्चों में होने वाली रेबीज की समस्या के कारण अत्यंत गंभीर स्थिति के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के प्राधिकारों को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों को शीघ्रतापूर्वक उठाएं और उन्हें आयुध स्थलों में रखें।

न्यायालय ने कहा कि समय के साथ कुत्तों के लिए आयुध स्थलों की संख्या बढ़ानी होगी। न्यायालय ने दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छह से आठ सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आयुध स्थल बनाएं।

आवारा कुत्तों की समस्या को “अत्यधिक गंभीर” बताते हुए न्यायमूर्ति जे बी पारदावाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह कई निर्देश पारित किए और चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने के काम में बाधा डालेगा, तो शीघ्र अदालत उसके खिलाफ अमानवान की कार्यवाही शुरू करेगी।

